



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2015/भाद्र 17, 1937

No. 309]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2015/BHADRA 17, 1937

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2015

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पन्द्रहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 4)

सं. 1-41/2015-बीएंडसीएस.—संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो—

- (क) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा
- (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड 3 के उप-खंड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 39 (का.आ. 44 (अ) तथा 45(अ)) के तहत प्रकाशित हुई थी,—

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 06) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः—

- (1) इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पन्द्रहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 4) कहा जाएगा।
(2) यह सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 06) (जिसे इसमें आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 2 में—
(ए) उप-खंड (डीडी) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
“(डीडी) ‘सामान्य सब्सक्राइबर’ का आशय उस सब्सक्राइबर से है जो वाणिज्यिक सब्सक्राइबर नहीं है।
(बी) उप-खंड (डीडीए) को विलोपित किया जायेगा।
(सी) उप-खंड (डीडीबी) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
“(डीडीबी) ‘वाणिज्यिक सब्सक्राइबर’ का आशय ऐसे सब्सक्राइबर से है, जो टीवी चैनलों के सिगनलों को एक निर्दिष्ट राशि के भुगतान पर सुनने या देखने के लिए किसी व्यक्ति को समर्थ बनाता है;”

(डी) उप-खंड (एफ) तथा इसके स्पष्टीकरण के लिए, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(एफ) “प्रभार” का आशय :-

- (i) “सब्सक्राइबर” के संदर्भ में, सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्त की गई केबल सेवाओं के लिए, केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को देय दरों (कर के अलावा) से है;
- (ii) “केबल ऑपरेटर” के संदर्भ में, केबल ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की जा रही प्रसारण अथवा केबल सेवाओं के लिए, केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा प्रसारक, जैसा भी मामला हो, को देय दरों (कर के अलावा), से है;
- (iii) “मल्टी सिस्टम ऑपरेटर” के संदर्भ में, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की जा रही प्रसारण सेवाओं के लिए, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रसारक को देय दरों (कर के अलावा), से है”।

(ई) उप-खंड (आई) के बाद निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(आई) सब्सक्राइबर का आशय उस व्यक्ति से है जो, सेवा प्रदाता को उसके द्वारा बताए स्थान पर, सेवा प्रदाता से सिगनल, किसी अन्य व्यक्ति को आगे प्रसारित किए बगैर, प्राप्त करता है और इसमें सामान्य सब्सक्राइबर और वाणिज्यिक सब्सक्राइबर शामिल हैं, जब तक कि इन्हें विशेष रूप से अपवर्जित न किया गया हो।”

3. मूल टैरिफ आदेश के खंड-3 में, -

(ए) स्पष्टीकरण-1 से पूर्व के उप-खंड (क), (ख) और (ग) तथा पैरा (क) तथा (ख) के लिए निम्नलिखित उप-खंड तथा पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे नामतः :-

“(क) सामान्य केबल सब्सक्राइबर से केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो;

(ख) केबल ऑपरेटर से मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा प्रसारक, जैसा भी मामला हो;

(ग) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से प्रसारक,

31 मार्च, 2014 को लागू ऊपरी सीमा होगी, -

(क) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से केबल ऑपरेटर तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर द्वारा सामान्य केबल सब्सक्राइबर को प्रसारित तथा पुनःप्रसारित फ्री-टू-एयर तथा पे-चैनल, दोनों के लिए ; और

(ख) केवल पे-चैनल के बुके अथवा पे-चैनल तथा फ्री-टू-एयर, दोनों प्रकार के चैनलों तथा स्टैंडअलोन चैनल, जो किसी बुके का भाग न हो, जिन्हें प्रसारकों द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों अथवा केबल ऑपरेटर अथवा दोनों को प्रसारित किया गया हो :”

(बी) उप-खंड (ग) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 1, 2 और 3 को विलोपित किया जाएगा;

(सी) तृतीय परंतुक तथा इसके पैरा-I और II के लिए, निम्नलिखित परंतुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“बशर्ते यह भी कि सामान्य सब्सक्राइबर के मामले में, प्रत्येक टेलीविजन कनेक्शन के लिए, उप-खंड (क) के तहत देय प्रभार, इसकी अधिकतम सीमा होंगे;

4. मूल टैरिफ आदेश के खण्ड 3बी के पश्चात्, निम्न खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, नामतः :-

“3बीए. वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए टैरिफ- (1) प्रसारक, वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए, अपने सभी पे चैनलों को, टीवी चैनलों के वितरकों को अला-कार्टे आधार पर पेशकश करेगा और प्रत्येक पे चैनल के लिए अलग अला-कार्टे मूल्य निर्धारित कर सकता है।

बशर्ते कि प्रसारक अपने सभी पे चैनलों को, बुके के भाग में जिसमें पे चैनल या पे चैनल और फ्री-टू-एयर चैनल्स शामिल हो, पेशकश कर सकता है और प्रत्येक ऐसे बुके का दर निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) प्रसारक वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को टीवी चैनलों के सिगनल उपलब्ध करने के लिए टीवी चैनलों के वितरकों और वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के साथ तीन पक्षीय समझौता कर सकता है।

(3) उप-खंड (1) के तहत किए गए किसी तीन पक्षीय समझौते को प्रसारक द्वारा ऐसे समझौता करने के तीस दिनों के अंदर प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।”

सुधीर गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./142/15 (198)]

टिप्पणी:-1 : दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश 2004 (2004 का 6) दिनांक 01 अक्टूबर, 2004 अधिसूचना संख्या: 1-29/2004-बीएण्डसीएस के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था तथा बाद में दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1-29/2004-बीएण्डसीएस, दिनांक 01 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1-29/2004-बीएण्डसीएस, दिनांक 29 नवंबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 1-13/2005-बीएण्डसीएस, दिनांक 07 मार्च, 2006 की

अधिसूचना संख्या 1-2/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 24 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-2/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 31 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-13/2005-बीएण्डसीएस, दिनांक 21 नवंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-19/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 1-1/2007-बीएण्डसीएस, दिनांक 26 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 1-31/2008-बीएण्डसीएस, दिनांक 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 1-2/2014-बीएण्डसीएस, दिनांक 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या 1-6/2014-बीएण्डसीएस, 16 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 1-18/2014-बीएण्डसीएस, 31 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या : 1-6/2014-बीएण्डसीएस तथा 06 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 1-1/2014-बीएण्डसीएस के द्वारा इसमें संशोधन किए गए थे।

टिप्पणी:-2 : इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पन्द्रहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 4) के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट किया गया है।

अनुलग्नक

व्याख्यात्मक टिप्पणी

पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसके पश्चात् भादूविप्रा अधिनियम कहा गया है) के माध्यम से स्थापित, एक सांविधिक निकाय है। अस्तित्व में आने के पश्चात्, भादूविप्रा का मुख्य कार्य क्षेत्र दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं के हितों की संरक्षा करना तथा दूरसंचार सेवाओं को सुचारु विकास को बढ़ावा देना है।
2. भारत सरकार ने दिनांक 09 जनवरी, 2004 की एक अधिसूचना के माध्यम से “प्रसारण सेवाओं” तथा “केबल सेवाओं” को “दूरसंचार सेवाओं” के रूप में अधिसूचित किया। तदनुसार, वर्ष 2004 से भादूविप्रा अपने संस्तुतिकारी तथा विनियामककारी शक्तियों का भी प्रयोग करते हुए देश में प्रसारण तथा केबल टेलीविजन क्षेत्र को विनियमित कर रहा है।
3. प्रसारण तथा केबल टेलीविजन सेवा क्षेत्र को विनियमित करने की शक्तियां प्रदत्त करने के तुरंत बाद से भादूविप्रा ने दिनांक 15 जनवरी, 2004 को अंतरिम रूप से दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवा टैरिफ आदेश, 2004 को अधिसूचित किया। इस आदेश के माध्यम से केबल उपभोक्ता द्वारा केबल आपरेटर, केबल आपरेटर द्वारा एमएसओ/प्रसारक तथा एमएसओ द्वारा प्रसारकों को फ्री-टु एयर (एफटीए) तथा पे-चैनलों के लिए प्रदान की जाने वाली अधिकतम राशि को, भादूविप्रा द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने तक, विहित किया गया था। उस तिथि तक केबल उपभोक्ताओं की कोई श्रेणी नहीं बनाई गई थी। तत्पश्चात्, 01 अक्टूबर, 2004 को भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ आदेश, 2004 (जिसे इसके पश्चात् “मूल गैर-सीएस टैरिफ आदेश” कहा गया है) को 15 जनवरी, 2004 को जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए जारी किया। इस टैरिफ आदेश में केबल टेलीविजन प्रभागों पर लगाई गई अधिकतम सीमा को भी यथावत बनाये रखा गया था। इस टैरिफ आदेश में भी टेलीविजन उपभोक्ताओं में कोई श्रेणी नहीं बनाई गई थी।
4. दिनांक 08 अगस्त, 2005 को होटल और रेस्त्रां संघ ने कुछ प्रसारकों द्वारा प्रभारित विभेदक टैरिफ को चुनौती देते हुए माननीय टीडीसेट के समक्ष याचिका सं 80(ग) और 32(ग)/2005 दायर की। 17 जनवरी, 2006 को माननीय टीडीसेट ने याचिका खारिज की, जिसमें वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को सब्सक्राइबर अथवा उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है। उन्होंने प्राधिकरण से इस बात पर भी विचार करने को कहा कि क्या वाणिज्यिक केबल टेलीविजन उपभोक्ताओं के लिये टैरिफ का निर्धारण करना आवश्यक है अथवा नहीं?
5. 07 मार्च, 2006 को भादूविप्रा ने माननीय टीडीसेट के दिनांक 17 जनवरी, 2008 के आदेश में की गई टिप्पणियों तथा फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार करते हुए दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2006 (2006 का 2) को अंतरिम रूप से अधिसूचित किया। इस आदेश में उपभोक्ता की दो श्रेणियों – साधारण केबल उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता को परिभाषित किया गया था। इस आदेश में यह भी उपबंध किया गया था कि वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता के लिए दिनांक 01 मार्च, 2006 को विद्यमान लिखित/मौखिक करारों में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भुगतान की जाने वाली राशि की दर (कर के अलावा) उसकी अधिकतम सीमा होगी तथा दिनांक 01 मार्च, 2006 को विद्यमान लिखित/मौखिक करारों में लागू सिद्धांतों को “दर” शब्द की व्याप्ति का निर्धारण करने के लिये लागू किया जाना चाहिये। वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता के अलावा अन्य सभी उपभोक्ताओं हेतु ऐसा ही उपबंध किया गया था।
6. दिनांक 21 अप्रैल, 2006 को भादूविप्रा द्वारा इस मुद्दे पर विस्तृत परामर्श हेतु एक परामर्श पत्र भी जारी किया गया। इसी दौरान, माननीय टीडीसेट के दिनांक 17 जनवरी, 2006 के आदेश को चुनौती देते हुए होटल और रेस्त्रां संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील संख्या 2061/2006 दायर की और दिनांक 28 अप्रैल, 2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने “यथापूर्व स्थिति बनाये रखने” का आदेश पारित किया। दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने “यथापूर्व स्थिति के आदेश में संशोधन करते हुए भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 के तहत टैरिफ आदेश तैयार करने तथा माननीय टीडीसेट द्वारा की गई किसी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित करने के आदेश दिये। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि दूसरा परामर्श पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि, टैरिफ आदेश जारी करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भादूविप्रा के सभी उपबंधों का पालन किया गया है।
7. तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु मसौदा टैरिफ आदेश को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित किया गया।
8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में विधिवत परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने 21 नवम्बर, 2006 को दो संशोधन आदेश नामतः दूरसंचार (प्रसारण केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (सातवां संशोधन) आदेश, 2006 (2006 का 8) तथा दूरसंचार (प्रसारण और

- केबल) सेवाएं (तृतीय) (सीएस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 (2006 का 6) जो क्रमशः गैर-सीएस तथा सीएस क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपभोक्ता पर लागू थे, को जारी किया। इन टैरिफ संशोधन आदेशों के निम्नलिखित मुख्य उपबंध थे:—
- (क) तीन सितारा तथा उससे ऊपर के श्रेणी के होटलों, हेरीटेज होटलों तथा 50 अथवा उससे अधिक कमरों की क्षमता वाले होटलों (जिसे इसके पश्चात् “होटलों की पृथक श्रेणी” कहा जायेगा) को आपस में सहमत प्रभारों के अनुसार प्रभारित किया जाना था।
 - (ख) होटलों की अन्य श्रेणियों के लिये प्रभार (होटलों की अन्य श्रेणियों के अलावा) साधारण तथा अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ता हेतु दर के समान होगा।
 - (ग) किसी प्रसारक के कार्यक्रमों, जिन्हें मनोरंजन कर कानून के तहत पंजीकृत किसी स्थान पर आम लोगों के देखने के लिए किसी विशेष अवसरों पर दिखाया जायेगा, जहां कम से कम 50 व्यक्तियों को भुगतान आधार पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, ऐसे स्थानों पर वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता द्वारा दोनों पक्षों के बीच आपस में निर्धारित टैरिफ प्रभारित किया जायेगा।
9. दिनांक 24 नवम्बर, 2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या : 2061/2006 पर निर्णय दिया तथा माननीय टीडीसेट के दिनांक 17 जनवरी, 2006 के आदेश को पलट दिया तथा प्रकरण के संबंध में स्वतंत्र रूप से नये सिरे से टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया जारी रखने के निदेश के साथ भादूविप्रा को वापस भेज दिया।
 10. दिनांक 21 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना के तहत पृथक श्रेणी के होटलों तथा फेडरेशन ऑफ होटल्स एण्ड रेस्त्रांस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने अन्य बातों के साथ-साथ भादूविप्रा द्वारा जारी दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के टैरिफ आदेश/अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय टीडीसेट के समक्ष अपील संख्या 17(ग)/2006 (ईस्ट इंडिया होटल लि0 बनाम भादूविप्रा एवं अन्य) तथा 18(ग)/2006 (कनाट प्रोमिनेन्ट होटल्स लि0 बनाम भादूविप्रा एवं अन्य) दायर की। माननीय टीडीसेट ने दिनांक 28 मई, 2010 के अपने निर्णय के माध्यम से अपीलों को स्वीकार किया तथा टैरिफ आदेश को रद्द किया और अन्य के साथ-साथ प्राधिकरण को व्यापक तरीके से नये सिरे से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मामले पर विचार करने को कहा।
 11. माननीय टीडीसेट के दिनांक 28 मई, 2010 के आदेश को चुनौती देते हुए एक प्रसारक (मैसर्स ईएसपीएन) द्वारा सिविल अपील संख्या: 6040—6041/2010 तथा अन्य संबद्ध अपील संख्या : 10476—10777/2010 तथा 8358—8359/2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसमें:
 - (क) दिनांक 16 अगस्त, 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय टीडीसेट के दिनांक 28 मई, 2010 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का एक आदेश पारित किया।
 - (ख) दिनांक 16 अप्रैल, 2014 के निर्णय के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6040—41/2010 तथा अन्य संबद्ध अपीलों को खारित कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भादूविप्रा को टैरिफ का पुनर्निर्धारण करने के लिए तीन माह के अंदर नये सिरे से मामले पर विचार करने का निदेश दिया।
 12. तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 11 जून, 2014 को एक परामर्श पत्र जारी किया तथा तत्पश्चात् विधिवत परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के उपरान्त, निम्नलिखित विनियम तथा आदेश अधिसूचित किये:—
 - (क) दिनांक 16 जुलाई, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (बारहवां संशोधन) आदेश, 2014 (2014 का 05)।
 - (ख) दिनांक 18 जुलाई, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रैसेबल प्रणालियां) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2014 (2014 का 6) जारी किया, जिसके माध्यम से मूल एड्रैसेबल (डिजीटल) टैरिफ आदेश को संशोधित किया गया।
 - (ग) दिनांक 18 जुलाई, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजीटल एड्रैसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 09) जारी किया, जिसके माध्यम से मूल एड्रैसेबल (डिजीटल) अंतःसंयोजन विनियम को संशोधित किया गया।
 - (घ) दिनांक 18 जुलाई, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 8) जारी किया, जिसके माध्यम से मूल गैर-सीएस अंतःसंयोजन विनियम को संशोधित किया गया।
 13. उपर्युक्त दोनों टैरिफ संशोधन आदेश को माननीय टीडीसेट के समक्ष इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाउंडेशन एवं अन्य द्वारा अपील सं0 7(ग)/2014 के माध्यम से चुनौती दी गई। दिनांक 16 जुलाई, 2014 तथा 18 जुलाई, 2014 के उपर्युक्त संशोधनों तथा गैर-सीएस तथा डीएस क्षेत्रों पर लागू अंतःसंयोजन विनियमों तथा टैरिफ आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या: 5161/2014 (स्टार इंडिया बनाम भादूविप्रा और अन्य) दायर की गई।
 14. माननीय टीडीसेट ने अपने दिनांक 09 मार्च, 2015 के आदेश के अनुसार दिनांक 16 जुलाई, 2014 तथा 18 जुलाई, 2014 के दोनों टैरिफ संशोधन आदेशों को निरस्त करते हुए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा दायर की गई अपील को स्वीकार किया। माननीय टीडीसेट ने अपील को स्वीकार करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ भादूविप्रा को आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के अंदर नये आदेश जारी करने का निदेश भी दिया। इसके अलावा, उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया था प्राधिकरण आदेश की तिथि से एक माह की अवधि के अंदर किसी भी अंतरिम व्यवस्था के संबंध में निर्णय ले सकता है।
 15. भादूविप्रा ने 13 मई, 2015 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 09 मार्च, 2015 के माननीय टीडीसेट के आदेश में संदर्भित अंतरिम व्यवस्था के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रेस विज्ञप्ति के संगत उद्धृण नीचे दिये गये हैं:—

“ अंतरिम उपाय के रूप में माननीय टीडीसेट के दिनांक 09 मार्च, 2015 के आदेश को चुनौती देते हुए भादूविप्रा द्वारा दायर की गई सिविल अपील के निष्कर्ष के अधीन दिनांक 01.10.2004 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ आदेश, 2014 (2014 का 6) तथा दिनांक 31.08.2006 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तृतीय) (सीएस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 (2006 का छठा) तथा दिनांक 21.07.2010 का “दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रैसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 01) लागू होंगे”

16. रिट याचिका संख्या : 5161/2014 में माननीय दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15 मई, 2015 को आदेश जारी किया कि माननीय टीडीसेट के दिनांक 09 मार्च, 2015 के अनुसार टैरिफ का निर्धारण करते हुए भादूविप्रा किसी भी प्रकार से याचिका में विवादित विनियमों द्वारा स्वयं को आबद्ध नहीं समझेगा।
17. भादूविप्रा ने माननीय टीडीसेट की अपील सं० 7(सी)/2004 में दिये गये 09 मार्च, 2015 के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एक अपील (सिविल अपील सं० 4851/2015 (भादूविप्रा बनाम आईबीएफ और अन्य) दायर की।
18. प्राधिकरण ने माननीय टीडीसेट के आदेश के अनुसार सभी हितधारकों की टिप्पणियां/मत प्राप्त करने के लिए दिनांक 14 जुलाई, 2015 को “वाणिज्यिक उपभोक्ता से संबंधित टैरिफ मुद्दे” शीर्षक पर एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की तथा परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। परामर्श पत्र में इस मुद्दे पर पूर्व के निर्धारणों पर बिना पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए एक नई तथा समग्र पद्धति अपनाई गई। कुल 22 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। तथापि, कोई भी प्रति-टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 18 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई, जिसमें 73 हितधारकों ने भाग लिया। साथ ही ओएचडी उपरांत 11 टिप्पणियां प्राप्त हुईं।
19. मुद्दे के व्यापक अध्ययन तथा परामर्श पत्र और साथ ही ओएचडी में चर्चा की प्रतिक्रिया में सभी हितधारकों की टिप्पणियों/दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए यह टैरिफ आदेश जारी किया जा रहा है।

मुद्दों का विश्लेषण

साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बीच भेद किये जाने तथा पृथक परिभाषा की आवश्यकता

20. परामर्श पत्र में, टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने में साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को परिभाषित करने तथा उनके बीच भेद किये जाने की आवश्यकता के संबंध में बुनियादी मुद्दे पर हितधारकों के विचार आमंत्रित किये गये थे। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, जिन हितधारकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनके मत/दृष्टिकोण संक्षेप में नीचे दिये गये हैं।

हितधारकों की टिप्पणियां

21. सभी प्रसारकों तथा उनके संघों ने यह पक्ष रखा कि टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को परिभाषित किया जाना तथा उनके बीच भेद किया जाना आवश्यक है।
22. अधिकांश डीपीओ ने कहा कि साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को परिभाषित किये जाने तथा उनके बीच भेद किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मत को न्यायोचित ठहराने के लिये नीचे कुछ कारण दिये गये:-
 - (क) एड्रैसेबल प्रणाली में, प्रत्येक एसटीबी एक उपभोक्ता होता है और इस प्रकार उसका पूर्णरूपेण लेखा-जोखा रखा जाता है।
 - (ख) किसी साधारण अथवा किसी वाणिज्यिक उपभोक्ता को उपलब्ध कराई गई टेलीविजन सेवा में कोई अंतर नहीं होता है।
23. कुछ डीपीओ ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसा भेद केवल उस स्थिति में किया जाना चाहिये जब कोई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों को टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के लिये अलग से प्रभार उद्ग्रहित करता है। इस प्रकार वह वाणिज्यिक लाभ हेतु टेलीविजन सिग्नलों का दोहन करता है।
24. लगभग सभी होटलों तथा उनके संघों ने यह निवेदन किया है कि साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच किसी प्रकार का भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिये गये तर्कों के पक्ष में उनके द्वारा कुछ कारण गिनाये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-
 - (क) पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिनांक 16.12.2014 के पत्र संख्या: 8-टीएच-193/2013 के माध्यम से जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होटलों में टेलीविजन सेवा एक अनिवार्यता है।
 - (ख) माननीय टीडीसेट के दिनांक 27 फरवरी, 2007 के निर्णय के अनुसार टेलीविजन सेवा, आगन्तुकों को उपलब्ध कराई जाने वाली एक अनिवार्य सेवा है।
 - (ग) होटल तथा रेस्त्रां अपने आगन्तुकों से टेलीविजन सब्सक्रिप्शन की लागत की वसूली नहीं करते हैं।
 - (घ) निवासी ग्राहक की तुलना में वाणिज्यिक उपभोक्ता के पास विशेष रूप से प्रसारकों से बेहतर मोल-भाव करने की क्षमता नहीं होती है।
25. उद्योग के पर्यवेक्षक सहित व्यक्ति विशेष तथा एक उद्योग संघ का मत था कि साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई भेद किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि उपभोक्ता का साधारण तथा वाणिज्यिक रूप में श्रेणीकरण किया जाना चाहिए तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता का उपभोक्ता के स्थान पर चलाई जा रही वाणिज्यिक क्रियाकलाप की वृहदतता तथा स्वरूप के अनुसार आगे श्रेणीकरण किया जा सकता है।

विश्लेषण

26. पिछले कुछ दशकों में देश में टेलीविजन सेवाओं का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है तथा शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिकांश घरों तथा अन्य प्रतिष्ठानों की पे-टेलीविजन सेवाओं तक पहुंच है। जब आरंभ में वर्ष 2006 में भादूविप्रा ने वाणिज्यिक उपभोक्ता हेतु पृथक श्रेणी तैयार की थी, तब से लेकर आज तक टेलीविजन पर जिस प्रकार का दृष्टिकोण था, उसमें व्यापक पैमाने पर परिवर्तन हो गया है। वर्ष 2006 में होटलों में पे-टेलीविजन चैनल देखना एक विलासिता समझी जाती थी तथा कई बार टेलीविजन के साथ तथा टेलीविजन के बिना कमरों की अलग-अलग दरें बतलाई जाती थी। अब पे-टेलीविजन सर्वव्यापी हो गया है तथा होटलों के कमरों में टेलीविजन सिग्नल सुविधा उपलब्ध कराने के आधार पर होटलों को वाणिज्यिक टेलीविजन उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं है। आजकल, न केवल होटल तथा रेस्त्रां बल्कि विभिन्न अन्य सार्वजनिक स्थानों यथा विमानपत्तन, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, चिकित्सकों के क्लीनिक आदि में भी टेलीविजन चैनलों को देखा जा सकता है। इन प्रतिष्ठानों में दौरान करने वाले किसी भी व्यक्ति ने साधारण रूप से टेलीविजन विषय-वस्तु की घर पर प्राप्ति हेतु नियत दरों का पहले ही भुगतान किया ही होगा। ऐसे स्थानों पर टेलीविजन कार्यक्रमों को देखना पहली बार उन कार्यक्रमों तक पहुंच नहीं होता बल्कि एक प्रकार से उनकी निरंतरता ही होती है। इसलिये, यह स्पष्ट होता है कि इन प्रतिष्ठानों का दौरा करने वाला व्यक्ति केवल टेलीविजन विषय-वस्तु देखने के लिये ही नहीं आता है। देश में टेलीविजन सेवाओं की सर्वव्याप्तता तथा पे-टेलीविजन विषय-वस्तु की व्यापक रूप से उपलब्धता के साथ इन प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी टेलीविजन सेवाएं ग्राहकों हेतु अलग से कोई महत्वपूर्ण आकर्षण नहीं है। अधिकांश मामलों में मूल रूप में टेलीविजन सेवाओं की किसी अन्य मूलभूत सुविधा की भांति ही पेशकश की जाती है। तथापि, ऐसे भी उदाहरण हैं जब यह प्रतिष्ठान विशेष टेलीविजन विषय-वस्तु उपलब्ध कराने तथा आकर्षण बढ़ाने के लिये अपने ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। इन विशिष्ट मामलों में, प्रतिष्ठान अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिये विशेष टेलीविजन विषय-वस्तु को प्रदर्शित कर उसका दोहन करते हैं। इस प्रकार वे जन-सामान्य द्वारा प्रभार के भुगतान पर टेलीविजन प्रसारण को दिखाकर अथवा सुनाकर वाणिज्यिक रूप से लाभान्वित होते हैं।
27. इसलिये, प्राधिकरण का मत है कि इन प्रतिष्ठानों में उपयोग की जा रही टेलीविजन सेवाओं हेतु टैरिफ को विनियमित करने के लिये, ऐसे प्रतिष्ठानों को वृहद रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है— (i) जहां ग्राहक को टेलीविजन सेवाओं के उपयोग हेतु अलग से भुगतान नहीं करना पड़ता है; या जहां टेलीविजन सेवाओं का उपयोग मुख्य उद्देश्य के अनुषंगी है, दूसरे शब्दों में जब टेलीविजन सेवाओं को अलग से प्रभावित नहीं किया जाता है; और (ii) जहां ग्राहक को टेलीविजन सेवाओं का उपयोग करने के लिये अलग से भुगतान करना पड़ता है तथा प्रतिष्ठान इस प्रकार की टेलीविजन सेवाओं से राजस्व अर्जित करता है। इस प्रकार, टेलीविजन सेवाओं के उपयोग के स्वरूप के आधार पर साधारण सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को पृथक रूप से अलग किये जाने और परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।

टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ताओं के वर्गीकरण हेतु आधार अथवा मानदण्ड

28. परामर्श पत्र में यह मुद्दा उठाया गया था कि यदि टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ता का वर्गीकरण किया जाना आवश्यक हो तो ऐसे टेलीविजन उपभोक्ता के वर्गीकरण का क्या आधार अथवा मानदण्ड होना चाहिये। परामर्श पत्र में टेलीविजन सिग्नल को प्रदर्शित किये जाने के स्थान, टेलीविजन सिग्नलों के उपयोग मानदण्ड के स्वरूप, टेलीविजन सिग्नलों को उपलब्ध कराने की पद्धति, टेलीविजन सिग्नल की विषय-वस्तु के स्वरूप, टेलीविजन सेवाओं से प्राप्त होने वाले लाभ के आधार पर विभिन्न संभावनाओं को भी उजागर किया गया था, साथ ही साथ, हितधारकों से अन्य मानदण्ड के बारे में भी सुझाव आमंत्रित किये गये। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, जिन हितधारकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनके मतों/दृष्टिकोण को संक्षेप में नीचे दिया गया है।

हितधारकों की टिप्पणियां

29. अधिकांश प्रसारक तथा उनके संघों का यह मत है कि टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के लिये साधारण और वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच अंतर करना अनिवार्य है। इसके अलावा, उनके द्वारा 'उपयोग के स्वरूप' तथा 'उपयोग का स्थान' को सबसे महत्वपूर्ण मानदण्ड के रूप में सुझाव दिया गया है। प्रसारकों ने यह भी सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आगे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाये:-

(क) होटल के कमरे।

(ख) सभी वाणिज्यिक ऑऊटलेट जिनमें रेस्त्रां, दुकान, फ़ैक्ट्रियां तथा कार्यालय शामिल हैं। तथापि, निम्नवत को छूट प्रदान की जा सकती है।

(i) जहां दस कर्मचारियों से कम कर्मचारी कार्यरत हों।

(ii) शहरी सीमा में भवन का क्षेत्रफल 2500 वर्ग फीट से कम हो तथा शहर से इतर 5000 वर्ग फीट तक हो।

*उपर्युक्त (i) तथा (ii) के तहत छूट महानगरों, राज्य की राजधानियों तथा क/ख श्रेणी के शहरों में लागू नहीं होगी।

(iii) एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत अत्यंत छोटे प्रतिष्ठान।

(ग) विमानपत्तन लॉऊज, बैंक्वेट तथा पार्टी हॉल, होटल की लाबियों, थियेटर तथा प्रेक्षागृह आदि सहित ऐसा क्षेत्र जहां जन साधारण कार्यक्रम देख सके।

30. एक प्रसारक ने यह सुझाव दिया कि टेलीविजन उपभोक्ता का वर्गीकरण इस तथ्य के आधार पर भी किया जा सकता है कि क्या प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त की गई सेवा इसके मुख्य कार्य क्षेत्र के लिये "अनुषंगी" अथवा "अनिवार्य" स्वरूप की थी। यदि वे अनुषंगी सेवा का उपयोग करने के विकल्प को अपनाते हैं जैसे किसी भी प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये टेलीविजन का उपयोग करते हैं, तो इसे वाणिज्यिक लाभ के लिये माना जायेगा। ऐसी सेवाओं हेतु सेवा प्रदाताओं (प्रसारकों) को पृथक रूप से प्रभार उद्ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिये चूंकि इसे स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक लाभ के लिये उपयोग किया जाता है।

31. डीपीओ तथा उनके संघ ने उल्लेख किया कि साधारण घर के उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्त्रां, विमानपत्तन, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, चिकित्सक के क्लीनिक में भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चूंकि सैटेलाइट फुटप्रिंट

संपूर्ण भारत में उपलब्ध है, अतः उपभोक्ता के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर डीटीएच रिसीवर को स्थानांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः, टीवी सिग्नल के उपयोग के स्थान के आधार पर वाणिज्यिक उपभोक्ता तथा सामान्य घरेलू उपभोक्ता में अंतर करना बहुत मुश्किल है।

32. उनमें से कुछ ने आगे सुझाव दिया कि उनमें केवल उस स्थिति में भेद किया जाना चाहिये जब वाणिज्यिक उपभोक्ता अपने उपभोक्ताओं को टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के लिये अलग से प्रभारों का उद्ग्रहण करें, और इस प्रकार वे वाणिज्यिक लाभ के लिये टेलीविजन सिग्नलों का दोहन करें।
33. लगभग सभी होटल तथा उनके संघों ने उल्लेख किया कि उन उपभोक्ताओं के मामलों में जब पृथक शुल्क/प्रवेश शुल्क प्रभारित कर टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक दोहन किया जाता है, उनके अलावा साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई भेद करने की जरूरत नहीं है।
34. एक व्यक्ति का मत था कि साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई भेद किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, उद्योग संघ ने सुझाव दिया कि छोटी तथा मझौली दुकान के स्वामियों को वाणिज्यिक उपभोक्ता नहीं समझा जाना चाहिये। जबकि 1 से 5 सितारा सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले सभी संगठनों को वाणिज्यिक उपभोक्ता माना जाना चाहिए।

विश्लेषण

35. विभिन्न हितधारकों की अधिकांश टिप्पणियां/सुझाव यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ताओं का वर्गीकरण किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि, टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये ग्राहकों को पृथक रूप से प्रभारित किये जाने पर इसे अपवाद मानकर प्रभारित किया जाना चाहिये। प्रसारकों का मत है कि टेलीविजन सेवाओं के “उपयोग के स्वरूप” साथ ही टेलीविजन सेवाओं के “उपयोग का स्थान” ही उपभोक्ता के वर्गीकरण का मानदण्ड होने चाहिये। प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ता को सामान्य तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता श्रेणियों में परिभाषित तथा वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता है। यह वर्गीकरण आसान, असंदिग्धार्थी तथा संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (वैल्यू-चेन) में व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित किये जाने हेतु सक्षम होना चाहिये। जबकि, प्रत्येक हितधारक के हित का पर्याप्त रूप से संरक्षण भी किया जाना चाहिये।
36. प्राधिकरण ने नोट किया कि वर्ष 2006 में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सिग्नल के उपयोग के स्वरूप को ध्यान में न रखते हुए “उपयोग के स्थान” के आधार पर विशेष रूप से होटलों को परिभाषित किया गया था, जिसे होटल उद्योग द्वारा समय-समय पर न्यायालय में चुनौती दी गई। अब प्रसारकों ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को “उपयोग के स्थान” तथा “उपयोग के स्वरूप” के आधार पर परिभाषित किये जाने की मांग की है। अन्य हितधारक लगातार मांग करते रहे हैं कि “उपयोग के स्थान” तथा “उपयोग के स्वरूप” अथवा अन्य मानदण्डों के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाना चाहिये। उनका मत है कि प्राधिकरण को केवल उन वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को परिभाषित करने के लिए केवल उन प्रतिष्ठानों पर विचार करना चाहिये, जो वाणिज्यिक लाभ के लिए टेलीविजन सिग्नलों का उपयोग करते हैं।
37. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने हितधारकों द्वारा सुझाए गये वर्गीकरण के विभिन्न विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। यह नोट किया गया है कि अधिकांश मामलों में, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में टेलीविजन सिग्नल का उपयोग केवल जानकारी-सह-मनोरंजन के उद्देश्यों के लिये ही किया जाता है तथा टेलीविजन सिग्नलों के लिये अलग से कोई शुल्क भी प्रभारित नहीं किया जाता है। पे-टेलीविजन चैनल सर्वव्यापी हो गये हैं तथा अधिकांश स्थानों पर जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं, वहां लगभग प्रत्येक घर की पे-टेलीविजन कार्यक्रमों तक पहुंच है। इसलिये, ऐसे प्रतिष्ठानों में टेलीविजन सेवाओं को उपलब्ध कराने से ऐसे प्रतिष्ठानों का दौरा करने वाले ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता है। इसके अलावा, ऐसे प्रतिष्ठानों में टेलीविजन कार्यक्रमों को देखना मूल रूप से उपभोक्ता द्वारा अपने घर में पहले से ही देखी जा रही ऐसी विषय-वस्तु की निरंतरता को बनाये रखना ही होता है। यहां यह उल्लेख करना विषयेतर नहीं होगा कि टेलीविजन के चैनलों को देखने से प्रसारक को अधिक लोगों द्वारा विषय-वस्तु को देखे जाने के परिणामस्वरूप विज्ञापनों के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने दिसम्बर, 2014 को तीन सितारा तथा उससे ऊपर के होटलों के कमरों में तथा अन्य होटलों की लॉबी में टेलीविजन सेवाओं को उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया है। वैसे, इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जहां विषय-वस्तु एकाधिकार स्वरूप की है और होटलों द्वारा ऐसी विषय-वस्तु उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया गया है, विनियामककारी तंत्र को वैल्यू-चेन में हितधारकों के हितों के बीच संतुलन कायम करना चाहिये।
38. प्राधिकरण ने नोट किया है कि ऐसे भी मामले हो सकते हैं जब टेलीविजन कार्यक्रमों को दिखाने के लिए अलग से प्रभारित कर टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जाता है। इसलिए, विभेदकारी मानदण्ड टेलीविजन सिग्नलों के उपयोग का स्वरूप हो सकता है अर्थात् जहां अलग से प्रभारित कर इससे राजस्व अर्जित करने हेतु टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जाता है।
39. तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य के साथ-साथ होटल एवं रेस्त्रां संघ और अन्य बनाम स्टार इंडिया प्रा0 लि0 और अन्य की अपील (सिविल) 2061/2006 में दिनांक 24.11.2006 को दिये गये अपने निर्णय में निम्नवत पाया:—

“..... होटलों के स्वामी अपने उपभोक्ताओं/आगन्तुकों के लिये टेलीविजन सिग्नल प्राप्त करते हैं। ऐसा करते हुए वे अन्य बातों के साथ-साथ अपने उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। कोई होटल का स्वामी अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न सुविधाएं जैसे बिस्तर, खाना-पीना, पंखे, टेलीविजन आदि उपलब्ध करवाता है। होटल में निवास करने वालों के लिए ऐसी सुख-सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये व्यवस्था करना, किसी होटल के स्वामी द्वारा आगन्तुक को किसी प्रकार का विक्रय किया जाना नहीं माना जायेगा। होटलों के स्वामी प्रसारक से उसी प्रकार टेलीविजन सिग्नल प्राप्त करते हैं जैसे वे लाइसेंसधारी से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं। आगन्तुक किसी भी विद्युतीय उपकरण उपयोग कर सकता है। इसका अभिप्राय होटल द्वारा उसे विद्युत विक्रय किया जाना नहीं होगा। उक्त प्रयोजनार्थ “उपभोक्ता” तथा “सब्सक्राइबर” होटल तथा उसका प्रबंधन ही रहेगा। इसी प्रकार, यदि प्रबंधन द्वारा सुविधा स्वरूप प्रदत्त सेवा के भाग स्वरूप सभी कमरों में टेलीविजन सेट उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिये आगन्तुक से अलग से प्रभार नहीं वसूला गया हो, तो इससे होटल में ठहर रहे आगन्तुक उपभोक्ता अथवा सब्सक्राइबर नहीं बन जाएंगे।.....”

40. उक्त निर्णय में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय (पंजाब राज्य बनाम मैसर्स एसोसियेटेड होटल्स ऑफ इंडिया [(1972)। एससीसी 472]) द्वारा इसी मुद्दे को नीचे पुनर्द्वत किया गया है:-

“..... जब कोई यात्री, वायुयान अथवा स्टीम-शिप से अपनी यात्री टिकट क्रय करता है तो उसका लेन-देन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करने का ही होता है। यदि उस यात्रा के दौरान यात्री को पेय पदार्थ अथवा भोजन अथवा सिगरेट प्रदान की जाती है तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि जितनी बार यह सब चीजें उसे दी गई हैं उसे अलग से बिक्री की गई है। लेन-देन अनिवार्य रूप से यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक ले जाने का हुआ था। यदि उसे करार में निष्पादन के दौरान किसी चीज की आपूर्ति की जाती है तो ऐसी आपूर्ति उस सेवा की अनुषंगी होगी, जिससे करार के पैटर्न अथवा स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार, जब धुलाई के लिये कपड़े दिये जाते हैं तो इसमें लेन-देन शामिल होता है, जिसमें अनिवार्य रूप से कार्य अथवा सेवा शामिल होती है और यदि धोबी किसी परिधान में टूटे हुए बटन को बदल देता है तो उसमें बटन अथवा धागे की कोई बिक्री नहीं हुई। सामग्री के अनुषंगी उपयोग की अनेक घटनाएं उद्धृत की जा सकती हैं, जिनमें से किसी घटना में भी मुख्य लेन-देन के भाग के रूप में विक्रय शामिल नहीं है।”

41. उपर्युक्त उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराया जाना, उस सेवा की अनुषंगी सेवा ही है, जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है। इस प्रकार, उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि सुख-सुविधा के रूप में किसी आगन्तुक को उपलब्ध कराई गई कोई भी सेवा, जिसके लिए आगन्तुकों को पृथक रूप से प्रभारित नहीं किया जाता है तो इसमें आगन्तुकों को उक्त सेवा की बिक्री नहीं मानी जाएगी।
42. उपर्युक्त विचार-विमर्श के मद्देनजर, प्राधिकरण का मत है कि उपभोक्ता के वर्गीकरण का मूलभूत मानदण्ड यह होना चाहिये कि क्या टेलीविजन सेवा का, इसे उपलब्ध कराये जाने के स्थान के अनेपक्षत, उपभोक्ता द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए अलग से प्रभारों का उद्ग्रहण कर राजस्व अर्जित करने के लिए टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जा रहा है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में उपभोक्ताओं के वर्गीकरण का मानदण्ड टेलीविजन सिग्नलों का 'उपयोग का स्वरूप' होना चाहिये न कि 'सिग्नलों के उपयोग का स्थान' होना चाहिये। तदनुसार, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि यदि सब्सक्राइबर अपने ग्राहकों को टेलीविजन सेवा का उपयोग करने पर अलग से प्रभार उद्ग्रहण करता है तो इसे ग्राहकों से राजस्व अर्जित करने के लिए टेलीविजन सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन माना जायेगा तथा सब्सक्राइबर को 'वाणिज्यिक उपभोक्ता' माना जायेगा। तदनुसार इस टैरिफ आदेश में 'साधारण उपभोक्ता' तथा 'वाणिज्यिक उपभोक्ता' को परिभाषित किया गया है।

एड्रसेबल तथा गैर-एड्रसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी टेलीविजन सेवाओं के वाणिज्यिक उपभोक्ता हेतु मौजूदा टैरिफ संरचना (थोक तथा खुदरा स्तरों) की समीक्षा की आवश्यकता

43. परामर्श पत्र में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या थोक तथा खुदरा दोनों स्तरों पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु मौजूदा टैरिफ संरचना पर्याप्त है अथवा इसकी समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। परामर्श प्रक्रियाओं के दौरान जिन हितधारकों ने प्रतिक्रिया दी उनके मत/दृष्टिकोण नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये हैं:-

हितधारकों की टिप्पणियां

44. अधिकांश प्रसारक तथा उनके संघ का यह मत था कि जहां तक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का संबंध है, टैरिफ संरचना की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को एड्रसेबल तथा गैर-एड्रसेबल दोनों प्रणालियों हेतु थोक तथा खुदरा स्तरों पर फॉरबीयेरेन्स होना चाहिए क्योंकि बाजार में सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है।
45. अधिकांश डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर और उनके संघ ने इस मुद्दे पर अपने मतों की पेशकश करते हुए यह उल्लेख किया है कि उन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अपने उपभोक्ताओं को टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पृथक रूप से प्रभारित करते हैं तथा इस प्रकार वाणिज्यिक लाभ के लिए सिग्नलों का दोहन करते हैं, के अलावा वाणिज्यिक उपभोक्ता हेतु मौजूदा टैरिफ संरचना की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
46. लगभग सभी होटल तथा उनके संघों ने यह निवेदन किया है कि वाणिज्यिक उपभोक्ता हेतु मौजूदा टैरिफ संरचना की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विश्लेषण

47. प्राधिकरण का यह मत है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य-श्रृंखला (वैल्यू-चेन) में सभी हितधारकों के हितों का पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाये, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु एक वृहद टैरिफ संरचना को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। टैरिफ संरचना व्यावहारिक रूप से कार्यान्वयन योग्य होनी चाहिए। तदनुसार, एक संरचना तैयार करके, उक्त टैरिफ आदेश में शामिल किया गया है।

एड्रसेबल तथा गैर-एड्रसेबल प्रणालियों के माध्यम से वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पृथक टैरिफ संरचना (थोक तथा खुदरा स्तरों पर) को तैयार करने की आवश्यकता तथा उसके संबंध में सुझाव

48. परामर्श पत्र में यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या थोक तथा खुदरा दोनों स्तरों पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु पृथक टैरिफ संरचना की आवश्यकता है। यदि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए ऐसे पृथक संरचना की आवश्यकता हो तो वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु पृथक टैरिफ संरचना को तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किये गये थे। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, जिन हितधारकों ने प्रतिक्रिया दी थी उनके मत/दृष्टिकोण को नीचे संक्षेप में दिया गया है:-

हितधारकों की टिप्पणियां

49. प्रसारक तथा उनके संघ का साधारण रूप से यह मत था कि एड्रेसेबल तथा गैर-एड्रेसेबल दोनों प्रणालियों के लिए थोक तथा खुदरा दोनों स्तरों पर कुल फॉरबीयेरेन्स होना चाहिए। फॉरबीयेरेन्स प्रणाली को न्यायोचित ठहराने के पीछे कुछ प्रतिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं:-

- (क) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पास स्वयं के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त मोल-भाव करने की शक्तियां होती हैं।
- (ख) टेलीविजन चैनल मूल्य के संबंध में विनियम को लागू करने के इच्छुक तथाकथित वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के ग्राहकों हेतु 'शून्य मूल्य विनियम' (नो प्राईस रेगुलेशन) लागू है।
- (ग) सवैधानिक दृष्टिकोण से टेलीविजन चैनल एक गैर-अनिवार्य सेवा है।
- (घ) यदि साधारण उपभोक्ता के टैरिफ विनियम को वाणिज्यिक उपभोक्ता पर भी लागू किया जाता है तो भुगतान करने वाले प्रसारक को न केवल साधारण उपभोक्ता बल्कि वाणिज्यिक उपभोक्ता के व्यापार को भी इस प्रकार से पर्याप्त रूप से सहायता (सब्सिडी) देनी होगी, जिससे भुगतान करने वाले प्रसारक को सीधी हानि होगी जबकि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तथा डीपीओ को उतना ही लाभ होगा।

50. लगभग सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर तथा उनके संघों का यह मत है कि टेलीविजन सेवाओं के लिए पृथक रूप से अपने उपभोक्ताओं को प्रभारित करने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो इस प्रकार टेलीविजन सिग्नलों को वाणिज्यिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं, उनके अलावा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ संरचना की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

51. होटलों ने अपना मत रखा है कि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु पृथक टैरिफ संरचना की कोई आवश्यकता नहीं है तथा भादूविप्रा पृथक रूप से अपने उपभोक्ताओं को प्रभारित करने वाले अथवा टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक लाभ के लिए दोहन करने वाले संस्थानों के लिए टैरिफ विहित कर सकता है तथा ग्राहकों को टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु टैरिफ की दरों का निर्णय डीपीओ को निर्धारित करने हेतु छोड़ देना चाहिए। इस पक्ष के समर्थन में कुछ तर्क नीचे दिये गये हैं :-

- (क) यदि फॉरबीयेरेन्स प्रदान कर दिया जाता है तो होटल के उपभोक्ता टेलीविजन कार्यक्रम नहीं देख पायेंगे, जिसके लिए उन्होंने पहले ही भुगतान किया है।
- (ख) कमरे का किराया अन्य कारकों के कारण बढ़ता-घटता है, जबकि सब्सक्रिप्शन शुल्क एक समान ही रहता है।
- (ग) होटल की औसत अधिभोग दर सालाना 50 प्रतिशत रहती है जबकि होटल वर्ष भर शत-प्रतिशत कमरों के लिए टेलीविजन कनेक्शन हेतु भुगतान करता है।
- (घ) पूर्व में भी फॉरबीयेरेन्स का प्रसारकों द्वारा दुरुपयोग किया गया।
- (च) प्रसारकों के स्वामित्व वाली टेलीविजन विषय-वस्तु एकाधिकार स्वरूप की होती है, इसलिए प्रसारकों द्वारा फॉरबीयेरेन्स का दुरुपयोग किया जा सकता है। टेलीविजन सिग्नलों का दोहन करने वाले उपभोक्ताओं के मामले में भी किया जाने वाला कोई भी मोल-भाव केवल डीपीओ तथा उपभोक्ता के बीच ही होना चाहिये।
- (छ) डीपीओ किये गये आपसी करार की शर्तों के अनुरूप राजस्व के भाग को प्रसारक को सौंप देता है।
- (ज) उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किये जाने वाले टेलीविजन सिग्नलों को तृतीय पक्ष को दिखाकर, टिकट को बेचने से प्राप्त हुए राजस्व का आपस में तय प्रभारों के अनुरूप उपभोक्ता द्वारा डीपीओ को किये जाने वाले भुगतान के संबंध में एक उपबंध शामिल किया जाना चाहिए।

52. एक व्यक्ति का मत था कि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु पृथक टैरिफ संरचना की कोई आवश्यकता नहीं है।

विश्लेषण

53. प्राधिकरण ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोणों की पर विचार किया। यह नोट किया गया कि प्रसारकों ने फॉरबीयेरेन्स की मांग की है। प्राधिकरण ने उठाये गये विभिन्न मुद्दों की विस्तार से जांच की है तथा उसका मत है इस टैरिफ आदेश में यथा परिभाषित वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के संबंध में प्रसारकों को फॉरबीयेरेन्स दिये जाने का मामला बनता है। तदनुसार, एक संरचना तैयार कर, उक्त टैरिफ आदेश में सम्मिलित किया गया। यहां यह नोट किया जा सकता है कि समय-समय पर यथा आशोधित "टेलीविजन चैनलों के डॉउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों" के अनुसार प्रसारक केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत एमएसओ/केबल आपरेटरों अथवा सरकार द्वारा जारी डीटीएच दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत डीटीएच आपरेटर अथवा मौजूदा दूरसंचार लाइसेंसों के तहत विधिवत् रूप से अनुमय अथवा दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता अथवा सूचना एवं प्रसारण विभाग, भारत सरकार द्वारा एचआईटीएस आपरेटरों हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत एचआईटीएस ऑपरेटर को ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए सैटेलाईट टेलीविजन चैनल सिग्नल रिसेप्शन डिकोडर उपलब्ध करायेंगे। इसलिए प्रसारकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे इन टैरिफ आदेशों में यथापरिभाषित वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से व्यवहार करते समय इन दिशानिर्देशों का पालन करें।

वाणिज्यिक उपभोक्ता हेतु मौजूदा संरचना की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए जांच करें ताकि मूल्य-श्रृंखला (वैल्यू-चेन) में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके ताकि हितधारकों के बीच विवादों तथा तकरारों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके और मौजूदा संरचना को अपर्याप्त पाये जाने पर व्यवहारिक तथा कार्यान्वयन योग्य संरचना का सुझाव दिया जा सके।

54. परामर्श पत्र में यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या विभिन्न हितधारकों के बीच विवाद व मतभेद को प्रभावी रूप से न्यूनतम करने के लिए वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क पर्याप्त है। यदि फ्रेमवर्क को अपर्याप्त समझा जाता है तो हितधारकों से व्यावहारिक और क्रियान्वयन योग्य फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए सुझाव दिए जाएं। हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों/मतों का सारांश निम्न प्रकार है:-

हितधारकों की टिप्पणी

55. अधिकांश प्रसारकों तथा उनके संघों का मत था कि पूर्ण फॉरबीयेरेन्स पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के साथ ही थोक व खुदरा स्तर पर विवादों को कम करेगा।
56. लगभग सभी वितरक प्लेटफॉर्म आपरेटरों एवं उनके संघों का मत था कि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा टैरिफ संरचना की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीटीएच ऑपरेटरों ने कहा कि निषेध प्रावधान अवश्य रखे जाने चाहिए ताकि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्रसारकों से लाइसेंस प्राप्त किए बगैर टीवी सिग्नलों के लिए वाणिज्यिक रूप से शोषण न किया जाए। प्रसारणकर्ता तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बीच बातचीत में यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्य श्रृंखला में किसी भी संस्था को हानि न हो।
57. होटल व उनके संघों का मत था कि मौजूदा संरचना पर्याप्त है और इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
58. एक उद्योग संघ ने विचार प्रकट किया कि यदि डीएसएस के मौजूदा प्रावधानों को सही रूप से क्रियान्वित किया जाता है तो इससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

विश्लेषण

59. प्राधिकरण द्वारा मौजूदा फ्रेमवर्क के आलोक में, विभिन्न हितधारकों से इस संबंध में प्राप्त विचारों और सुझावों की जांच की। प्रसारकों को इस टैरिफ आदेश में निहित वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के मामले में थोक स्तर के मूल्य में फॉरबीयेरेन्स की अनुमति दी गई है। डीपीओ, प्रसारकों के साथ अनुबंध करके वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से प्रसारक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और डीपीओ के साथ तीन पक्षीय समझौता कर सकते हैं क्योंकि सिग्नल सिर्फ डीपीओ के माध्यम से दिया जा सकता है। किसी भी अवस्था में, डीपीओ को प्रसारक के साथ वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सिग्नल देने के लिए समझौता करना है। जहां तक टीवी सिग्नलों के दुरुपयोग का प्रश्न है वहां पर्याप्त प्रावधान है और किसी प्रकार का सिग्नल का दुरुपयोग वर्तमान नियमों के अनुसार देखा जायेगा। प्राधिकरण का मत है कि मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क उपयुक्त है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए मामले-दर-मामले आधार पर खुदरा टैरिफ निर्धारित करने हेतु प्रसारकों को अनुबंधित करने की आवश्यकता

हितधारकों की टिप्पणियां

60. अधिकांश प्रसारकों और उनके संघों का मत था कि सभी स्तरों पर टैरिफ फॉरबीयेरेन्स को अवश्य लागू किया जाना चाहिए तथा प्रसारक को वाणिज्यिक उपभोक्ता के साथ बातचीत करने की अवश्य अनुमति दी जानी चाहिए।
61. इस मुद्दे पर डीपीओ द्वारा मिश्रित राय दी गई। एक डीपीओ ने सुझाव दिया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए थोक स्तर पर प्रसारकों का अनुबंधन सीमित होना चाहिए, जबकि दूसरे डीपीओ की राय थी कि मामले-दर-मामले आधार पर प्रसारकों की भागीदारी स्वीकार्य है।
62. सभी होटल व उनके संघों का मत था कि केवल उन मामलों में, जिनमें प्रसारक अलग से प्रभारित करते हैं या टीवी सिग्नलों से अनुचित वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करते हैं, को छोड़कर फुटकर टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्रसारकों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
63. एक उद्योग संघ ने कहा कि प्रसारकों को अनुबंधित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे सामग्री (कन्टेंट) निर्माता होते हैं।

विश्लेषण

64. प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों के विचारों व सुझावों की जांच की तथा उसका मत है कि वाणिज्यिक उपभोक्ता के अलावा, जैसा कि इस टैरिफ आदेश में परिभाषित है, कोई भी टैरिफ निर्धारित करने तथा खुदरा स्तर पर टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्रसारकों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसारकों को वाणिज्यिक उपभोक्ता और डीपीओ के साथ तीन पक्षीय समझौता का विकल्प यह ध्यान में रख कर दिया गया है कि प्रसारकों के पास सिग्नल का कॉपीराइट है और सिर्फ डीपीओ टेलीविजन चैनलों के डाउनलिकिंग गाइडलाइन्स के अनुसार टीवी सिग्नल दे सकता है। आगे, टीवी सेवाओं के दुरुपयोग के प्रकृति और पैमाने मामले दर मामले भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए यह लचीलापन प्रसारकों को दिया गया है।

गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए टीवी सिग्नल का वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु दुरुपयोग न हो, सुनिश्चित करने के लिए तंत्र

हितधारकों की टिप्पणी

65. अधिकांश प्रसारकों व उनके संघों ने सुझाव दिया कि प्रसारकों को समय-समय पर डीपीओ का आडिट करने तथा साथ ही चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में दंड अधिरोपित करने तथा निरंतर चूक करने की स्थिति में, लाइसेंस को रद्द करने का उपबंध किया जाए।
66. डीपीओ का मत था कि लाइसेंस की शर्तों के रूप में तथा अनुमति, एंटी-पायरेसी कानून एवं विधिक फ्रेमवर्क के माध्यम से पहले ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं, जो कि इस प्रकार के दुरुपयोग की रोकथाम करते हैं।

67. सभी होटल और उनके संगठनों का मत था कि सभी हितधारकों की ओर से पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा किसी विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विनियमों/आदेशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड अधिरोपित किए जाने से, इस प्रकार के टीवी सिग्नल के दुरुपयोग से बचा जा सकेगा।
68. एक उद्योग संघ ने सुझाव दिया कि इस प्रकार के दुरुपयोग की घटना की रोकथाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र निगरानी निकाय स्थापित किया जाए।

विश्लेषण

69. प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों की जांच की और उसका मत है कि वर्तमान फ्रेमवर्क में पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं।

केबल टीवी प्रसारों की ऊपरी सीमा को निर्धारित करने के लिए संदर्भ तिथि

70. माननीय टीडीसेट ने अपने दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के आदेश के माध्यम से अपील सं0 1(ग)/ 2014 (सेन्टर फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया बनाम भादूविप्रा और अन्य संबद्ध प्रकरणों में) से प्राधिकरण के दो टैरिफ आदेशों नामतः दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2014 को निरस्त कर दिया। इन दोनों संशोधनों के माध्यम से दिनांक 31.03.2015 को मौजूद प्रसारों पर एनालॉग केबल टेलीविजन प्रणालियों (गैर-सीएस क्षेत्रों में) वैल्यू-चेन में सभी स्तरों पर उपलब्ध कराई जा रही सेवा के लिए केबल टेलीविजन प्रसारों में 27.5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को अनुमति प्रदान की गई थी। तदनुसार, इस टैरिफ आदेश में केबल टेलीविजन प्रसारों हेतु अधिकतम सीमा को विहित करने की संदर्भ तिथि को 31.03.2014 निर्धारित किया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2015

The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fifteenth Amendment) Order, 2015 (No. 4 of 2015)

No. 1-41/2015 - B&CS.—In exercise of the powers conferred by sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39 ,—

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 [S.O. 44(E) and 45(E)] dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii),—

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004), namely:—

1. (1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fifteenth Amendment) Order, 2015 (4 of 2015).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004) (hereinafter referred to as the principal Tariff Order),—

(a) for sub-clause (dd), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(dd) “ordinary subscriber” means a subscriber who is not a commercial subscriber.

(b) sub-clause (dda), shall be deleted.

(c) for sub-clause (ddb), the following sub-clause shall be substituted, namely:-----

“(ddb) “ commercial subscriber” means a subscriber who causes the signals of TV channels to be heard or seen by any person on payment of a specific sum of money”;

(d) for sub-clause (f) and its Explanations, the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(f) “Charges”, with reference to—

(i) subscriber means the rates (excluding taxes) payable by the subscriber to the cable operator or multi system operator, as the case may be, for cable services received by him;

(ii) cable operator means the rates (excluding taxes) payable by the cable operator to the multi system operator or broadcaster, as the case may be, for broadcasting services or cable services received by him;

(iii) multi system operator, means the rates (excluding taxes) payable by the multi system operator to the broadcaster, for the broadcasting services received by him;”

(e) after sub-clause (i) , the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(ie) subscriber means a person who receives the signals of a service provider at a place, indicated by him to the service provider without further transmitting it to any other person and includes ordinary subscriber and commercial subscriber unless specifically excluded;”.

3. In clause 3 of the principal Tariff Order,—

(a) for the sub-clauses (a), (b) and (c) and paras (A) and (B), appearing before Explanation 1, the following sub-clauses and paras shall be substituted, namely:—

“(a) Ordinary cable subscribers to cable operators or multi system operators, as the case may be;

(b) cable operators to multi system operators or broadcasters, as the case may be;

(c) multi system operators to broadcasters,

prevalent as on 31st day of March 2014, shall be the ceiling,-

(A) for both free to air channels and pay channels transmitted or re-transmitted by multi system operators to cable operators, and by multi system operators and cable operators to the Ordinary subscribers; and

(B) for bouquets of channels, consisting only of pay channels or both pay channels and free to air channels, and stand-alone channels, not forming part of any bouquet, transmitted by broadcasters to multi system operators or cable operators or both.”

(b) the Explanations 1, 2 and 3 below sub-clause (c), shall be deleted;

(c) for the third proviso and its paras I and II, the following proviso shall be substituted, namely:---

“Provided also that in the case of the ordinary subscribers, for each television connection, the charges payable under sub-clause (a), shall be the ceiling;”

4. After clause 3B of the principal Tariff order, the following clause shall be inserted, namely:-

“3BA. Tariff for commercial subscriber – (1) A broadcaster shall offer all its pay channels, for commercial subscribers on a-la-carte basis to distributors of TV channels, and may specify separate a-la-carte rate for each pay channel :

Provided that the broadcaster may also offer all its pay channels as part of bouquet consisting of pay channels or both pay and free to air channels and specify the rate for each such bouquet of channels offered by it.

(2) A broadcaster may enter into a tripartite agreement with the distributors of TV channels and the commercial subscribers for supply of signals of TV channels to the commercial subscribers.

(3) Any tripartite agreement entered into under sub-clause (2) shall be filed with the Authority by the broadcaster within thirty days of entering into such agreement.”

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./142/15 (198)]

Note 1.— The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 (6 of 2004) was published *vide* notification No. 1-29/ 2004-B&CS dated the 1st October, 2004 and subsequently amended *vide* notifications No. 1-29/ 2004-B&CS dated the 26th October, 2004, no. 1-29/ 2004-B&CS dated the 1st December, 2004, no. 1-13/ 2005-B&CS dated the 29th November, 2005, no. 1-2/ 2006-B&CS dated the 7th March, 2006, no. 1-2/ 2006-B&CS dated the 24th March, 2006, no. 1-13/ 2005-B&CS dated the 31st July, 2006, no. 1-19/ 2006-B&CS dated the 21st November, 2006, no. 1-1/2007-B&CS dated the 04th October, 2007, no. 1-31/2008-B&CS dated

the 26th December 2008, no. 1-2/2014 - B&CS dated 10th February 2014, No. 1-6/2014 - B&CS dated 31st March 2014, No. 1-18/2014 - B&CS dated the 16th July 2014 , No. 1-6/2014 - B&CS dated the 31st December 2014 and No. 1-1/2014 - B&CS dated the 6th January 2015.

Note 2.— The Explanatory Memorandum annexed to this Order explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fifteenth Amendment) Order, 2015 (4 of 2015).

Annexure

Explanatory Memorandum

Background

1. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is a statutory body established by the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (hereinafter referred to as the TRAI Act). Since its inception some of the prime focus areas of TRAI have been, to protect the interests of consumers and service providers of the telecommunication sector and to promote the orderly growth of telecommunication services.
2. The Government of India, through a Notification dated 9 January 2004, notified “broadcasting services” and “cable services” as “telecommunication services”. Accordingly, since 2004 TRAI has been regulating the broadcasting and cable TV sector in India by exercising its recommendatory as well as regulatory powers.
3. Soon after it came to be vested with regulation of broadcasting and cable TV services sector, TRAI notified, in the interim, the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff Order, 2004 on 15 January 2004. *Vide* this order charges payable by Cable subscribers to Cable Operators, Cable Operators to MSOs/Broadcasters and MSOs to Broadcasters as on 26 December 2003 were prescribed to be the ceiling for Free-to-Air (FTA) and pay channels, until final determination by TRAI. On that date, there was no categorization made amongst the cable subscribers. Thereafter, on 01 October 2004, TRAI notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (hereinafter referred to as ‘Principal Non-CAS Tariff Order’) superseding the interim tariff order issued on 15 January 2004. This tariff order also, retained the ceilings imposed on cable TV charges. In this tariff order also, no categorization was made amongst the TV subscribers.
4. On 08 August 2005, the Association of Hotels and Restaurants filed Petition Nos. 80(C) and 32(C) of 2005, before the Hon’ble TDSAT challenging the differential tariffs charged by some broadcasters. On 17 January 2006, the Hon’ble TDSAT dismissed the petition wherein it concluded that the members of the petitioner associations couldn’t be regarded as subscribers or consumers. It also asked the Authority to consider whether it was necessary or not to fix tariff for commercial cable TV subscribers.
5. On 07 March 2006, TRAI, upon considering the observations made by TDSAT in its Order dated 17 January 2006 and a representation received from Federation of Hotel and Restaurants Association of India (FHRAI), in the interim, notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2006(2 of 2006). In this order, two classes of subscribers - ordinary cable subscribers and commercial cable subscribers were defined. This order also provided that for the commercial cable subscribers, the rates (excluding taxes) payable by one party to the other by virtue of the written/oral agreement prevalent on 01 March 2006 shall be the ceiling and the principle applicable in the written/oral agreements prevalent on 01 March 2006, should be applied for determining the scope of the term “rates”. Similar provision was also made for all subscribers other than commercial cable subscribers.
6. On 21 April 2006, a Consultation Paper was issued by TRAI for detailed consultations on the issue. In the meantime, Civil Appeal No. 2061 of 2006 was filed challenging the Hon’ble TDSAT’s order dated 17 January 2006 by Associations of Hotels and Restaurants before the Hon’ble Supreme Court of India and the Hon’ble Supreme Court passed a “status quo” order on 28 April 2006. This status quo order was modified by the Hon’ble Supreme Court, on 19 October 2006, directing the Authority to carry out the processes for framing the tariff under Section 11 of the TRAI Act independently and not relying on or on the basis of any observation made by TDSAT. In the said order it was also mentioned that there is no need of issuing another consultation paper, however while issuing the

- Tariff Order it should be ensured that all the provisions of the TRAI Act have been complied with.
7. Accordingly in pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court, draft tariff amendment orders seeking comments of the stakeholders was placed on the website of TRAI.
 8. After following the due consultation process, in pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court, the Authority issued two Amendment Orders on 21 November 2006, viz The Telecommunications (Broadcasting & Cable) Services (Second) Tariff (Seventh Amendment) Order, 2006 (8 of 2006) and The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Third) (CAS Areas) Tariff Order, 2006 (6 of 2006), applicable to commercial subscribers in Non-CAS and CAS areas respectively. These tariff amendment orders had the following main provisions:
 - (a) With respect to hotels with ratings of 3 stars and above, heritage hotels and hotels with a capacity of 50 or more rooms (hereinafter referred to as "the Excluded Categories of Hotels"), the charges were to be mutually negotiated.
 - (b) The charges for other categories of hotels (except excluded categories of hotels) shall be at the same rate as for ordinary subscribers and other commercial subscribers.
 - (c) In respect of programmes of a broadcaster, shown on the occasion of a special event for common viewing, at any place registered under the Entertainment Tax Law and to which access is allowed on payment basis for a minimum of 50 persons by the commercial cable subscribers, the tariff shall be as mutually determined between the parties.
 9. On 24 November 2006, the Hon'ble Supreme Court of India decided Civil Appeal No. 2061 of 2006 and reversed the order of the TDSAT dated 17 January 2006 and remanded the matter back to TRAI directing it to carry on the process for fresh determination of tariff independently.
 10. Hotels which formed a part of the excluded category under the Notifications dated 21 November 2006 and the Federation of Hotel and Restaurants Association of India (FHRAI), filed Appeals No.17(c) of 2006 (East India Hotel Ltd vs. TRAI and Ors) and 18(c) of 2006 (The Connaught Prominent Hotels Ltd vs. TRAI and Ors) before the Hon'ble TDSAT challenging inter alia the Tariff Order/ Notification dated 21 November 2006, issued by TRAI. The Hon'ble TDSAT, by its judgment dated 28 May 2010, allowed appeals and quashed the tariff order and, amongst others, asked the Authority to consider the case of commercial establishments afresh in a broad based manner.
 11. Civil Appeal Nos. 6040-6041 of 2010 filed by one of the broadcasters (M/s ESPN) and other connected appeal Nos. 10476-10477 of 2010 and 8358-8359 of 2010 were filed before the Hon'ble Supreme Court challenging the judgment of the Hon'ble TDSAT dated 28 May 2010, wherein:
 - (a) On 16 August 2010, the Hon'ble Supreme Court passed an *ad interim* order of stay on the order of the TDSAT dated 28 May 2010.
 - (b) By its judgment dated 16 April 2014, the Hon'ble Supreme Court dismissed Civil Appeal No. 6040-41 of 2010 and other connected appeals. The Hon'ble Supreme Court further directed TRAI to consider the matter de-novo within 3 months and to re-determine tariff.
 12. Accordingly, TRAI issued a consultation paper on 11 June 2014 and subsequently, after following the due consultative process notified the following Regulations and Orders—
 - (a) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Twelfth Amendment) Order, 2014 (5 of 2014) on 16 July 2014.
 - (b) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2014 (6 of 2014) on 18 July 2014, that amended the Principal Addressable (Digital) Tariff Order.
 - (c) The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (Fourth Amendment) Regulation, 2014 (9 of 2014) on 18 July 2014, that amended the Principal Addressable (Digital) Interconnect Regulation.
 - (d) The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Eighth Amendment) Regulation, 2014 (8 of 2014) on 18 July 2014, that amended the Principal Non-CAS Interconnect Regulation.

13. The above two Tariff Amendment Orders were challenged by the Indian Broadcasting Foundation and Others, in Appeal No. 7(C) of 2014, before the Hon'ble TDSAT. A Writ Petition No. 5161 of 2014 (Star India vs. TRAI and Ors.) was filed before the Hon'ble High Court of Delhi challenging the above amendments dated 16 July 2014 and 18 July 2014, to the Tariff Orders and to the Interconnect Regulations applicable to Non-CAS areas and to DAS areas.
14. The Hon'ble TDSAT in its order dated 09 March 2015, allowed the appeal filed by the Indian Broadcasting Foundation, quashing the two tariff amendment orders dated 16 July 2014 and 18 July 2014. The Hon'ble TDSAT while allowing the appeal also, inter-alia, directed TRAI to issue fresh orders within six months from the date of the judgment. Further, it was also mentioned in the said judgment that the Authority may also take a decision with regard to any interim arrangement within one month from the date of the judgment.
15. In Writ Petition No. 5161 of 2014, the Hon'ble High Court of Delhi, issued an order on 15 May 2015, holding that while determining the tariff in terms of the order of TDSAT dated 09 March 2015, TRAI shall not consider itself bound by the regulations impugned in the petition in any manner whatsoever.
16. TRAI has filed an appeal (Civil appeal No 4851 of 2015 (TRAI vs. IBF and others)) in the Hon'ble Supreme Court challenging the order dated 09 March 2015, delivered in appeal No 7(C) of 2014, of the Ld. TDSAT.
17. TRAI issued a press release, dated 13 May 2015, clarifying its position with respect to the interim arrangement referred to in the Hon'ble TDSAT order dated 09 March 2015. The relevant extracts of the press release are given below-

"....an ad interim measure, the "Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second Tariff Order 2004" (6 of 2004) dated 01.10.2004, the "Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Third) (CAS Areas) Tariff Order 2006 (6 of 2006) dated 31.08.2006 and the "Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010) dated 21.07.2010 respectively shall apply subject to the outcome of the civil appeal filed by TRAI before the Hon'ble Supreme Court challenging the order dated 9th March, 2015 of the Hon'ble TDSAT."
18. The Authority, as per the Hon'ble TDSAT order initiated a consultation process and issued a consultation paper (CP) titled "Tariff issues related to commercial subscribers" on 14 July 2015 seeking comments/ views of all the stakeholders. The CP took a fresh and holistic approach without being biased with previous determinations to the issue. A total of 22 comments were received, however no counter-comment was received. An Open-House discussion (OHD) was conducted on 18 August 2015 at New Delhi wherein 73 stakeholders participated. A total of 11 post-OHD comments were also received.
19. This tariff order is being issued after comprehensive study and analysis of the issues while taking into consideration comments/ views of all the stakeholders in response to consultation paper as well as discussions in OHD.

Analysis of Issues

Need for differentiation between ordinary and commercial subscribers and requirement for separate definition

20. The consultation paper sought the views of all stakeholders on the basic issue of whether there is a need to define and differentiate between ordinary and commercial subscribers for provision of TV signals. The views/opinions of the stakeholders who responded during the consultation process are summarized below.

Stakeholder comments

21. All broadcasters and their association have brought out that it is essential to define and differentiate between ordinary and commercial subscribers for provision of TV signals.
22. Most of the DPOs have stated that there is no need to define and differentiate between the ordinary and commercial subscribers. Some of the reasons put forward to justify their view are as follows:

- (a) In an addressable regime, each STB is a subscriber and is thereby fully accounted for.

- (b) There is no difference in the TV service that is provided to an ordinary or a commercial subscriber.
23. Some DPOs also suggested that the only exception when such a differentiation must actually be made is when a commercial establishment charges separately for the TV services provided to his clients thereby exploiting the TV signals for commercial gains.
 24. Almost all hotels and their associations have submitted that no differentiation is required between the ordinary and commercial subscribers. Some of the reasons put forth in support of their argument are as follows:
 - (a) Television service in hotels is a necessity by virtue of the Ministry of Tourism guidelines issued vide letter no 8-TH-I93)/2013 dated 16.12.2014.
 - (b) TV service is an essential service to be provided to the guests as per the decision of the Ld. TDSAT dated 27 February 2007.
 - (c) Hotels and restaurants do not recover the cost of TV subscription from their guests.
 - (d) Commercial subscribers have no better bargaining power than residential subscribers especially vis-à-vis the broadcasters.
 25. Individuals including an industry observer and an industry association have opined that there is no need for differentiation between ordinary and commercial subscribers. However, one individual has suggested that there should be a categorization of the subscribers as ordinary and commercial and the commercial subscribers can be further categorized based on the scale and type of commercial activity that is carried out at such a subscriber's location.

Analysis

26. The penetration of TV services in the country in the last few decades has been on the rise exponentially and most of the households and other establishments in urban and semi-urban areas now have access to pay TV services. There has been paradigm shift from the way TV was looked at in 2006 when initially TRAI gave separate classification for commercial subscribers. Viewing Pay TV channels in Hotels in 2006 was considered a luxury and many a time separate rates for similar rooms with TV and without TV were quoted. Now pay TV has become ubiquitous and classifying hotels as commercial TV subscribers merely on the basis that they provide TV signal viewing facility in hotel rooms does not holds ground. Now a days, it is not only the hotels and restaurants but various other public places such as Airports, Malls, Shopping complexes, Hospitals, Doctors' Clinics etc., where one can have access to viewing of TV channels. Most of the individual visiting these establishments would have in the normal case already paid for domestic access to the TV content. Viewing of TV programs, if at all, at such places is not novelty and in no way adds to special experience. It can safely be presumed that an individual visiting these establishments cannot be doing so solely for the purpose of watching TV content. Moreover, with pervasiveness of TV services in the country and widespread availability of paid TV content, it no longer is a distinctive value proposition for these establishments to attract clientele on the basis of such TV services. In most cases, the TV services in a basic form are offered to the client akin to any other basic amenity. However, there may be instances where the establishments do charge their clients for providing premium TV content with enhanced attractiveness. In these specific cases, such establishments may be said to be exploiting the display of premium TV content to bring in additional revenues and thereby they do stand to benefit commercially by causing the TV broadcast to be heard or seen by the public on payment of charges.
27. The Authority is therefore of the view that for regulation of tariff for TV services being used at these establishments, such establishments may broadly be classified in two categories -(i) where the client does not have to pay separately to use the TV services or where use of TV services is incidental to the primary purpose; in other words, when the TV services are not being separately charged and (ii) where the client does pays separately for use of the TV services and the establishments earn revenues from provision of such TV services. Hence, depending upon the type of the usage of TV services, there is a need to differentiate and define 'ordinary subscriber' and a 'commercial subscriber' separately.

Basis or criterion for the classification of subscribers of TV services

28. The issue raised in the consultation paper was that in case a classification of subscribers of TV services is necessary, then what should be the basis or criterion for such a classification.

Consultation paper flagged various possibilities of such classification based on place of viewing TV signal, type of usage criteria for TV signals, method of provisioning of TV signals, type of content of TV signal, perceived value of TV services and also sought suggestions from the stakeholders for any other criteria which they may like to suggest. The views/opinions of the stakeholders who responded during the consultation process are summarized below.

Stakeholder comments

29. Most of the broadcasters and their association have opined that it is essential to differentiate between ordinary and commercial subscribers for provision of TV signals. Further, differentiation based on 'type of usage' and the 'place of usage' has been suggested by them as the most appropriate criteria. Broadcasters have also suggested that the commercial establishments should further be classified into the following:-
 - (a) Hotel rooms.
 - (b) All commercial outlets that include restaurants, shops, factories and offices with exemption however being granted to the following:-
 - (i) Those with less than twenty employees.
 - (ii) Premises of area less than 2500 sq. ft. within city limits and 5000 sq. ft. outside city limits.
 - * with a caveat that exemptions under (i) and (ii) above must not apply in metropolitan cities, state capitals and class A/B cities.
 - (iii) Micro-enterprises under the MSME Act 2006.
 - (c) Public viewing areas including airport lounges, banquet and party halls, hotel lobbies, theatres and auditoriums etc.
30. One of the broadcasters has suggested that the classification of TV subscribers can also be done on the basis of the fact that whether the service availed by the establishment is "incidental" or "essential" to the core area of its business. In the event that they choose to use an incidental service such as TV to enhance their businesses in any way, this will be for commercial gains. Service providers (broadcasters) of such services should have the right to charge separately as it is used for a clear commercial gain.
31. DPOs and their associations have stated that there is no need to differentiate between ordinary household subscriber and commercial establishments such as Hotels, Restaurants, Airports, Malls, Shopping complexes, Hospitals, Doctors' Clinics, where one can have access to viewing of TV channels without being charged separately. They also mentioned that since satellite footprint is available across India, hence, possibility of shifting DTH receiver from one location to other location by subscribers can not be ruled out. Hence, any differentiation between commercial subscribers and ordinary household subscriber based on location of uses of TV signals is difficult to be implemented on ground.
32. Some of them have further suggested that the only exception when such a differentiation must actually be made is when a commercial subscriber charges his customers separately for the TV service provided to his clients thereby exploiting the TV service for commercial gains.
33. Almost all hotels and their associations have submitted that there is no differentiation required between the ordinary and commercial subscribers except in case of those subscribers who commercially exploit the TV signals by charging separate fee/entry fee.
34. An individual has opined that there is no need for any differentiation between ordinary and commercial subscribers. An industry association has however suggested that small and medium shop owners should not be considered as commercial subscribers while all organizations providing 1-5 star services should be treated as commercial subscribers.

Analysis

35. Majority of Comments/ suggestions of various stakeholders indicate that there is no need for classification of subscribers while suggesting that the only exception that needs to be made is when clients are charged separately for the provision of TV services. Broadcasters are of the view that 'type of usage' of the TV services as well as the 'place of usage' of the TV services should be the criteria for classification of subscribers. The Authority, having come to the conclusion that while there is a need to define and differentiate subscribers of TV services into ordinary and commercial subscriber categories, is of the opinion that the classification must be simple, unambiguous, and practically implementable across the entire value chain whilst interest of every stakeholder is adequately protected.
36. The Authority has noted that in 2006, the commercial subscribers were defined by relying on "place of usage" of TV signal especially in Hotels irrespective of the type of usage, which has been contested time and again by the Hotel Industry. Broadcasters have now asked that commercial subscribers to be defined based on both "place of usage" and "type of usage". Other stakeholders are persistently demanding that no distinction should be made either based on place of usage or on type of usage or any other criteria. They are of the view that Authority must consider only those entities for defining commercial subscribers who explicitly exploit the TV signals for commercial gains.
37. In view of above, the Authority has carefully considered various options for classification suggested by the stakeholders. It is noted that in most of the cases, the TV signal in commercial establishments is used only for the infotainment purpose without separately charging for viewing of TV signals. Pay TV channel viewing has become ubiquitous and in most of the places where such commercial establishment exists, almost every household has access to pay TV programs. Therefore, provision of TV services in such establishment does not make any value proposition for the clients visiting such establishment. Further, viewing of TV programs in such establishments is not novelty and most of the clients would have already subscribed for such content. It may not be out of place to mention here that from such viewing of TV channels Broadcasters also get advantage by way of more advertisements due to increased viewership. Further, Ministry of Tourism has mandated provision of TV services in rooms for 3 star hotels and above and in lobby for other hotels in Dec 2014. As such, considering the scenario where content is monopolistic in nature and hotels are mandated to provide such content, the regulatory framework must balance the interest of stakeholders in the value chain.
38. The Authority has noted that there may be instances where TV signals are commercially exploited by separately charging for exhibiting the TV programs. Therefore the distinguishing criteria can be the 'type of usage of TV signals' i.e., where the signals are commercially exploited by charging separately for its exhibition for earning revenues out of it.
39. Moreover, the Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 24.11.2006 in appeal (Civil) 2061 of 2006 Hotel and Restaurants Association and Anr Vs Star India Pvt Ltd. and Ors has, amongst others, observed as under:

"....The owners of the hotels take TV signals for their customers/ guests. While doing so, they inter alia provide services to their customers. An owner of a hotel provides various amenities to its customers such as beds, meals, fans, television, etc. Making a provision for extending such facilities or amenities to the boarders would not constitute a sale by an owner to a guest. The owners of the hotels take TV signals from the broadcasters in the same manner as they take supply of electrical energy from the licensees. A guest may use an electrical appliance. The same would not constitute the sale of electricity by the hotel to him. For the said purpose, the 'consumer' and 'subscriber' would continue to be the hotel and its management. Similarly, if a television set is provided in all the rooms, as part of the services rendered by the management by way of an amenity, wherefor the guests are not charged separately, the same would not convert the guests staying in a hotel into consumers or subscribers....."

40. The said judgment further quotes another judgment of the Hon'ble Supreme Court (in The State of Punjab v. M/s. Associated Hotels of India Ltd. [(1972) 1 SCC 472]) on similar issue, which is reproduced as under:

".... When a traveller, by plane or by steam-ship, purchases his passage-ticket, the transaction is one for his passage from one place to another. If, in the course of carrying out that transaction, the traveller is supplied with drinks or meals or cigarettes, no one would think that the transaction involves separate sales each time any of those things is supplied. The transaction is essentially one of carrying the passenger to his destination and if in performance of the contract of carriage something is supplied

to him, such supply is only incidental to that services, not changing either the pattern or the nature of the contract. Similarly, when clothes are given for washing to a laundry, there is a transaction which essentially involves work or service, and if the laundryman stitches a button to a garment which has fallen off, there is no sale of the button or the thread. A number of such cases involving incidental uses of materials can be cited, none of which can be said to involve a sale as part of the main transaction."

41. From the observations of the Hon'ble Supreme Court, cited above, it is clear that provision of TV services in a commercial establishment is only incidental to the service that the commercial establishment is providing to its clients. Thus, it has also been settled by the said judgment that any service rendered to a guest by way of an amenity, wherefore the guests are not charged separately, the same would not constitute as sale of the said service to the guest.
42. In view of above deliberations, the Authority is of the view that the basic criteria for classification of subscribers should be whether the TV services, irrespective of its place of provisioning, are being commercially exploited, by the subscriber to earn revenues by charging separately for such services. In other words, the criteria for classification of subscribers should be the 'type of usage' of TV signals by the subscriber and not the subscriber's 'place of usage of signals'. In view of the discussions in paragraphs above, the Authority has decided that the subscribers who charge their clients separately to use the TV services, amounting to commercial exploitation of TV services to earn revenues out of it from their clients, shall be classified as 'commercial subscribers'. And all other subscribers shall be classified as 'ordinary subscribers'. Accordingly, 'subscriber', 'ordinary subscriber' and 'commercial subscriber' have been defined in this Tariff Order.

Need for review of existing Tariff framework (wholesale and retail levels) for Commercial subscribers of TV services provided through addressable and non-addressable systems

43. The issue raised in the consultation paper was whether the existing tariff framework for commercial subscribers both at the wholesale and retail levels was adequate or a review was needed. The views/opinions of the stakeholders who responded during the consultation process are summarized below.

Stakeholder comments

44. Most broadcasters and their association have opined that there is a need to review the tariff framework as far as commercial subscribers are concerned. They have suggested that the tariffs for commercial subscribers should be brought under forbearance at the wholesale and retail levels both for the addressable and non-addressable systems as sufficient competition already exists at all levels.
45. Most distribution platform operators and their associations while offering their views on this issue have stated that there is no need to review the existing tariff framework for commercial subscribers except for those commercial establishments that charge their customers separately for the TV services provided to their clients thereby exploiting the TV signals for commercial gains.
46. Almost all hotels and their associations have submitted that there is no need to review the existing tariff framework for commercial subscribers.

Analysis

47. The Authority is of the view that a comprehensive tariff framework for commercial subscribers needs to be put in place to ensure that the interests of all the stakeholders in the value-chain are adequately protected. The framework must be practically implementable, lend itself to effective monitoring and enforcement in the field. Accordingly, a framework has been worked out and included in this Tariff Order.

Need and suggestions towards framing a separate Tariff framework (at wholesale and retail levels) for Commercial subscribers for TV services provided through addressable and non-addressable systems.

48. The issue raised in the consultation paper was whether a need exists for a separate tariff framework for commercial subscribers both at the wholesale and retail levels. In case the need does exist for such a separate framework for commercial subscribers, suggestions were invited from the stakeholders towards framing a separate tariff framework for commercial

subscribers. The views/opinions of the stakeholders who responded during the process of consultation are summarized below.

Stakeholder comments

49. Broadcasters and their association in general have opined that there should be total forbearance both at the wholesale and retail levels both for addressable and non-addressable systems. Some of the reasons stated for justifying such a forbearance regime are as follows:
- (a) Commercial establishments possess sufficient bargaining powers to protect themselves.
 - (b) No price regulations exist for clients of so called commercial subscribers who are seeking TV channel price regulation.
 - (c) TV channels are a non-essential service from a constitutional point of view.
 - (d) In case the tariff regulation of ordinary subscribers is extended to commercial subscribers, then pay broadcaster will have to effectively subsidize not only ordinary subscribers but also the businesses of the commercial subscribers in a manner that results in direct losses to pay broadcasters while resulting in a corresponding gain to the commercial subscribers and the DPOs.
50. Almost all distribution platform operators and their associations are of the view that there is no need to review the existing tariff framework for commercial subscribers except for those commercial establishments that charge their customers separately for the TV services provided to their clients thereby exploiting the TV signals for commercial gains.
51. Hotels have put forth the view that there is no need to have a different tariff framework for commercial subscribers and TRAI may only prescribe tariff for institutions charging separately or commercially exploiting the TV signals and it should be left open to the DPOs to decide the tariff rates for providing TV signals to the clients. Some of the points given in support of such an argument are given below:
- (a) If forbearance is granted, hotel customers will suffer for not being able to watch TV programs for which they have already paid.
 - (b) Room rates fluctuate with other factors whereas subscription fee remains same.
 - (c) Hotel occupancies average out over a year to around 50% whereas the hotels pay for the TV connections for 100 % of their rooms throughout the year.
 - (d) Forbearance in the past has been misused by the broadcasters.
- (a) The TV content owned by the broadcasters is monopolistic in nature. Therefore forbearance may be misused by broadcasters. Any negotiation that occurs must be between the DPO and the subscriber even in case of revenue share for the subscribers exploiting TV signals.
 - (b) The DPO in turn passes on the revenue share to the broadcasters in accordance with the mutual agreements.
 - (c) A provision should be incorporated for payment of mutually negotiated charges by the subscriber to the DPO in the event that the subscriber is charging separately from third persons by selling tickets for viewing of the TV signal being received by it.
52. An individual has opined that there is no need to have a different tariff framework for commercial subscribers.

Analysis

53. The Authority has considered the views of various stakeholders submitted during the consultation process. It is noted that broadcasters have asked for tariff to be on forbearance. The Authority has considered various issues raised in detail and after analysis is of the view that there is a case for forbearance to be given to broadcasters in respect of commercial subscribers as defined in this tariff order. Accordingly, a framework has been worked out and included in the said tariff order. Here it may be noted that as per the “Policy Guidelines for Down-linking of Television Channels” amended from time to time, broadcasters shall provide satellite TV channel signal reception decoders only to MSOs/Cable Operators registered under the Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 or to a DTH operator registered under the DTH guidelines issued by Government of India or to a Internet Protocol Television (IPTV) Service provider duly permitted under their existing Telecom Licenses or

Authorized by Department of Telecommunications or to a HITS operator duly permitted under the policy guidelines for HITS operators, issued by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India to Provide such service. Therefore, it shall be ensured by the broadcasters that they adhere to these guidelines while dealing with commercial subscribers as defined in these tariff orders.

Examine adequacy of the present framework for commercial subscribers so as to ensure transparency and accountability in the value chain to effectively minimize disputes and conflicts amongst stakeholders and suggestions for a practical and implementable framework in case the present framework is believed to be inadequate

54. The issue raised in the consultation paper was whether the present framework for commercial subscribers is adequate to effectively minimize disputes and conflicts amongst various stakeholders. In case the framework is believed to be inadequate, suggestions were invited from the stakeholders towards framing a practical and implementable framework for the same. The views/opinions of the stakeholders who responded are summarized below:

Stakeholder comments

55. Majority of the broadcasters and their association are of the opinion that complete forbearance at the wholesale and retail levels will minimize disputes while bringing in transparency and accountability.
56. Almost all distribution platform operators and their associations are largely of the view that there is no need to review the existing tariff framework for commercial subscribers. DTH operators have submitted that deterrent provisions must be put in place so that the commercial subscribers do not commercially exploit TV signals without acquiring a license from the broadcasters. Negotiation between a broadcaster and the commercial establishment will ensure that no entity in the value chain is at loss.
57. Hotels and their associations feel that the present framework is adequate and there is no need to review it.
58. An industry association has opined that existing provisions of DAS if properly implemented will ensure transparency and accountability.

Analysis

59. The Authority has examined the views of various stakeholders in the light of the existing framework and suggestions received on this account. The Broadcasters have been permitted forbearance in pricing at wholesale level in respect of commercial subscribers defined in this Tariff Order. The DPO may enter into agreement with Broadcasters to declare retail tariff for commercial subscribers. Alternatively, Broadcasters may have tripartite agreements with commercial subscribers and DPO as signal can only be given through DPO. In any case, DPOs have to have an agreement with Broadcaster for provision of signals to commercial subscribers. As far as misuse of TV signal is concerned, there are adequate provisions and any case of misuse of signal shall be dealt according to extant rules. Therefore, The Authority is of the view that the existing framework is adequate to address the concerns of all the stakeholders in the value chain

Need for engagement of broadcasters in determination of retail tariffs for commercial subscribers on a case-to-case basis.

Stakeholder comments

60. Most broadcasters along with their association are of the view that tariff forbearance must be introduced at all levels and the broadcasters must be allowed to negotiate with the commercial subscribers.
61. The DPOs have offered mixed opinions regarding this issue. While one of the DPOs has suggested that engagement of broadcasters should be limited only at the wholesale level for all kinds of subscribers, another DPO has opined that involvement of broadcasters on a case-to-case basis is acceptable.
62. All hotels and their associations are of the opinion that there is no need to engage broadcasters in the determination of retail tariff except for those cases where the commercial subscribers do separately charge or commercially exploit the TV signals.

63. An industry association has said that there is a need to engage broadcasters as they are the content creators.

Analysis

64. The Authority having examined the views and suggestions of the various stakeholders is of the view that except for commercial subscribers as defined in this tariff order, there is no need for any tariff differentiation and involvement of broadcasters in determination of tariff at retail level. Broadcasters have been given options to have tripartite agreement with commercial subscribers and DPOs keeping in view that the broadcasters have copyrights of the content and only the DPOs can provide the TV signals as per the “Policy Guidelines for Down-linking of Television Channels”. Further, nature and scale of exploitation of TV services can be very different from case to case. Hence, this flexibility has been given to broadcasters.

Mechanism to ensure that TV signals provided for non-commercial purposes are not misused for commercial purposes.

Stakeholder comments

65. Most broadcasters along with their association have suggested that broadcasters must be allowed to conduct periodic audits of DPOs and also take action against the defaulters. They have further suggested that the Authority should levy fines and introduce a provision for cancellation of licenses in case of repeated defaults.
66. The DPOs are of the opinion that adequate safeguards do already exist in the form of conditions for license and permissions, anti-piracy laws and the legal framework that is place to prevent such misuse.
67. All hotels and their associations are of the view that due diligence is required on the part of all the stakeholders and no regulatory intervention is required. Imposition of penalties for non-compliance of regulations/orders can ensure that such misuse of TV signals is avoided.
68. An industry association has suggested that an independent monitoring body be created to ensure that no such misuse happens.

Analysis

69. The Authority has examined the comments of various stakeholders and is of the view that adequate provisions exist in present framework.

Reference date for prescribing ceilings of cable TV charges

70. Hon’ble TDSAT vide its order dated 28th April, 2015 in the matter of Appeal No. 1(C) of 2014 (Centre for Transforming India Vs. TRAI and other connected matters) set aside the Authority’s two tariff orders namely the Telecommunication (Broadcasting & Cable) Services (Second) Tariff (Eleventh Amendment) Order, 2014 and the Telecommunication (Broadcasting & Cable) Services (Second) Tariff (Thirteenth Amendment) Order, 2014. These amendments, put together, in effect, permitted a 27.5% hike in the cable TV charges, at all levels in the value chain, for the services being provided through analogue cable TV systems (non-CAS areas), over and above, the charges prevailing on 31.3.2014. Accordingly, in this Tariff Order, the reference date for prescribing ceilings of cable TV charges has been fixed as 31.3.2014.